

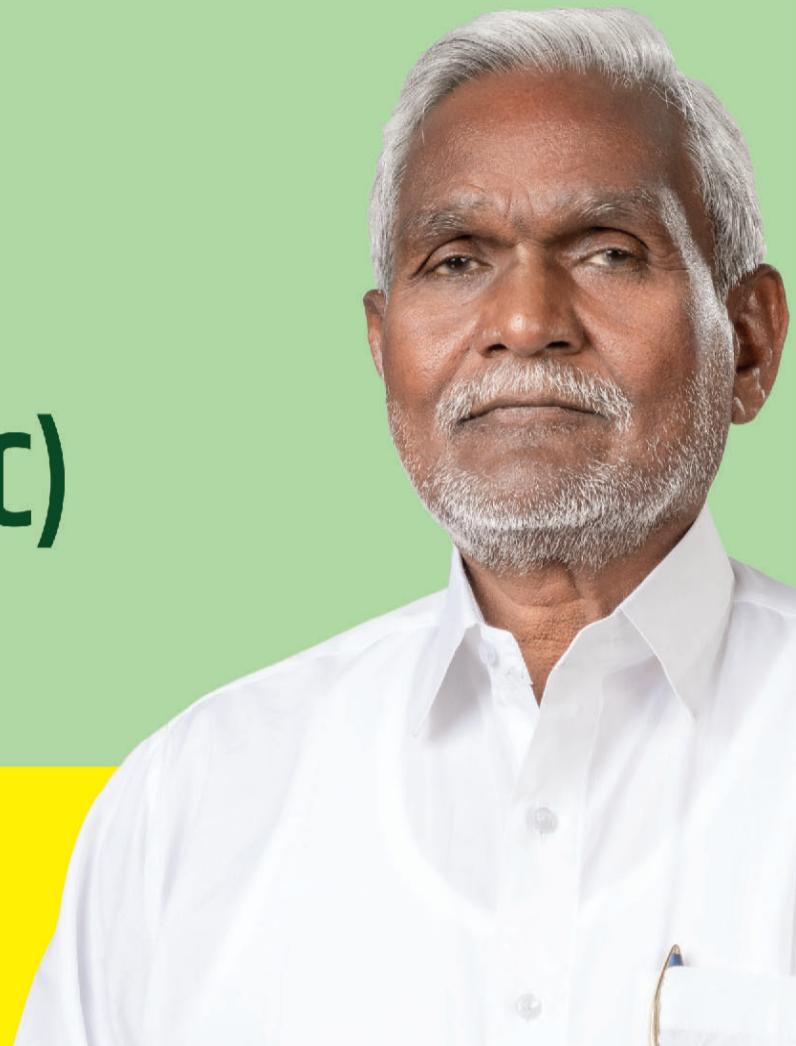
# आजाद सिपाही

रांची  
सोमवार, वर्ष 09, अंक 141



## गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (GSCC) तथा मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना

### का शुभारंभ कार्यक्रम



#### गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषता

आरखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त  
संस्थान से 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे  
विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च  
शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं वैसे  
छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता  
प्रदान करना ताकि छात्रों को उच्च  
शिक्षा के क्षेत्र/संस्थान जैसे Engineering,  
Medical, Law, Research, IITs, IIIMs  
आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले।

#### मुख्य अतिथि श्री चम्पाई सोरेन

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

### के कर कमलों द्वारा

#### गणितानन्द उपस्थिति

#### श्री सत्यानंद भोजा

माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण  
एवं कौशल विकास विभाग तथा  
उद्योग विभाग, झारखण्ड

#### श्री बादल पत्रलेख

माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं  
सहकारिता विभाग, झारखण्ड

#### मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना की विशेषता

राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त  
करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के  
उद्देश्य से मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना  
जिसमें राज्य के राजकीय/निजी /P.P.P  
मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में  
नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित  
विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण  
छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु  
₹15,000 प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष  
प्रदान की जायेगी।

दिनांक: 11 मार्च 2024  
समय: 11:30 पूर्वाह्न  
स्थान: टाना भगत स्टेडियम, एकेलगांव, रांची

विद्यार्थियों को क्रण के रूप में अधिकतम  
₹15 लाख तक की राशि बैंकों के माध्यम  
से बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के  
उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मात्र  
4% साधारण ब्याज की दर से राशि का भुगतान  
करना होगा, शेष ब्याज की राशि का वहन राज्य  
सरकार द्वारा किया जाएगा। क्रण वापसी की  
अवधि 15 वर्ष तक की निर्धारित की गई है जिसके  
लिए विद्यार्थियों से किसी प्रकार की जमानती  
सुरक्षा (Collateral Security) नहीं ली जाएगी।  
क्रण प्राप्ति के लिए किसी तरह की इनकम  
क्राइटरिया निर्धारित नहीं की गई है।

3 क्रण वापसी की प्रक्रिया पान्यक्रम  
पूर्ण होने के 1 वर्ष बाद प्रारंभ करने  
का विकल्प तथा अध्ययन की अवधि  
में ही क्रण का ब्याज चुकाने पर  
विद्यार्थी को ब्याज के दर में 1% की  
छूट भी दिए जाने का प्रावधान है।



झारखण्ड राज्य के राजकीय / निजी  
/ P.P.P मोड पर संचालित अभियंत्रण  
महाविद्यालयों ने बी.टेक / बी.इ. कोर्स में  
झारखण्ड राज्य के विद्यालय से  
10वीं एवं 12वीं कक्षा (अथवा  
समकक्ष) उत्तीर्ण छात्राओं को  
बी.टेक / बी.इ. कोर्स हेतु ₹30,000  
प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान  
की जायेगी।

जिस छात्र के परिवार का विगत वर्ष में  
सभी प्रकार के आय के स्रोतों को  
मिलाकर सकल वार्षिक आय  
अधिकतम ₹8 लाख तक प्रति वर्ष है या  
लाभुक दाण्डीय/राज्य खाद्य सुरक्षा  
योजना से आचारित हैं उन्हें ईकाणिक  
वर्ष 2023-24 से लाभ मिलेगा।

11 मार्च, 2024  
फाल्गुन, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा  
संवत् 2080  
पृष्ठ : 14, ग्रूप : ₹3.00

रांची

सोमवार, वर्ष 09, अंक 141

पीएम मोदी ने किया  
1008 परिवारों का  
सपना साकार

# आजाद सिपाही

कलम कलम बढ़ाये जा



## ओबीसी के हक और अधिकार के लिए उलगुलान का एलान



# कुबनी देकर भी लेकर रहेंगे हक-अधिकार: ब्रह्मदेव प्रसाद

### ■ मांगें पूरी नहीं हुई, तो सड़क पर लड़ाई

रांची(आजाद सिपाही)। पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एकता अधिकार मंच ने हक और अधिकार के लिए उलगुलान का एलान कर दिया है। मौका था- रविवार को एकता अधिकार मंच के छोटानागपुर प्रमंडलीय महासम्मेलन का। इसमें आवादी के



प्रमंडलीय महासम्मेलन में उमड़े जनसालाव ने एक साथ हाथ उठा कर केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद का अधिवादन स्वीकार किया। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि 11 सूखी मांगें अब सरकार को मान लेनी चाहिए, ये मांगें हमारा अधिकार हैं। गोरीभी समाज को बर्बाद कर रहा, हमारा ओबीसी समाज समृद्धि और संपूर्णता खो चुका है। बोरेजगारी बहस पर है, इसका करार है जनसंख्या के आधार पर अरक्षण का भिलान है। ओबीसी समाज सड़क पर लड़ाई शुरू करेगा। झारखंड के दूर जिलों से अभी सिर्फ आवाज उठनी शुरू हुई है, कल का हार बचक जाम और धरना प्रश्ने का गहरा अपनायें। पिछड़ा वर्ग ओबीसी परिवार को अन्यान्य अपनायें। जीमीन लूट और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अब वे अकेले नहीं हैं। मंच उनके साथ खड़ा है। कई भी परेशानी हो, हम उनके मदद के लिए तैयार हैं। ओबीसी समाज से अनेक महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि जनजनि में भी महिलाओं को बरबार का आधिकार देना चाहिए और केंद्र सरकार सुनिश्चित करें। बोरेजगार शक्ति युवकों को ऋण मुक्त प्रोत्साहन देनी, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय और शिक्षा में मदद मिले, जुर्ज अभिभावकों को पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

### ओबीसी की प्रमुख मांगें

- जाति आधारित जनगणना करा कर जनसंख्या के अनुपात ने पिछड़ा वर्ग के पुण्य- नहिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी और मानीदारी सुनिश्चित की जाए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ऐपोर्ट जारी की जाए।
- जनसंख्या के विवाद से सारी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में 52 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो।
- नगर निकाय-पर्याय धुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए निर्वाचित रोटर के अनुसार सीटों को राज्य सरकार आरक्षित करें।
- पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बोरेजगार धुनावों को 10000 रुपये मासिक बोरेजगारी भत्ता की व्यवस्था की जाए और किसानों का न्यूनतम समर्थन गूल्य बढ़ाया जाए।
- पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन ने आरक्षण के साथ ही निःशुल्क शिक्षा और बुनियादी सुविधा की व्यवस्था कर उन्हें रखने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
- पिछड़ा वर्ग के व्यापारियों और बोरेजगारों को स्थानांतरी बनाने के लिए बिना व्याज के 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- पिछड़ा वर्ग की तृतीय जनीन को उन्हें वापस कराया जाए और तृतीय जनीन जायदाद पर लेकर राजीन लंगों को उपलब्ध कराया जाए।
- पिछड़ा वर्ग के ऊपर हो रहे अन्याय, आपावधिक घटनाएं और हत्या से संबंधित मामलों में उन्हें त्वारित व्यापारियों के लिए काफ़िर ट्रैक कर्ट का व्यापान की जाए। साथ ही व्यवसायियों को सुधार प्राप्त की जाए।
- पिछड़ा वर्ग के व्यापारियों का गतिशील और सक्रिय करते हुए पिछड़ा वर्ग वित निगम की व्यापान का भवित्व बोरेजगार धुनावों को व्यापा गूर्ज बदल देना चाहिए।
- पिछड़ा वर्ग के व्यवसायियों द्वारा दिये गये कर (जीएसटी और इनकम टैक्स) के अनुपात में 50 वर्ग के ऊपर सभी को पेंशन की व्यवस्था की जाए।

### चक्का जाम और धरना-प्रदर्शन का भी रास्ता अपनायेंगे

शामिल करेगा, उसी पार्टी के समर्थन दिया जायेगा। ओबीसी की जो बात करेगा, वही सता पर राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की आवाज बुलंद की गयी। महासम्मेलन में शहर और गांव से काफ़ी संख्या में

ओबीसी समाज के महिला-पुरुष और युवा शामिल हुए। इधर, ओबीसी परिवार में जन्मे भोजपुरी कलाकार खेलारी लाल यादव ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के समर्थन में अपनी गीतों की प्रस्तुति दी।



### समाज के लोगों ने निभायी भागीदारी

अजय वर्मा ने मंच संचालन किया। महासम्मेलन में राज्य के अन्य वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने अपनी उपरिवर्ति दर्ज करायी, जिसमें वासवी जी, राजेश कुमार, शकुंतला जयसावल, श्रवण कुमार, दीपा राजीनी कुमार, विनोद कुमार, राज नारायण पटेल, अंजय वर्मा, गरखनाथ चौधरी, वरुण विहारी, संवेश पटेल, आरक्ष असारी, अमिलाल साहू, रवीद गुरु, वीरेंद्र साहू, बल टाङ्गर, कमलश आर्य, कृपाल साहू, रीना देवी, राकेश चौधरी और राकेश गुप्ता ने मंच साझा किया।

संघों के वक्त केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने भिस कॉल सदस्यता को लेकर 80 47358317 जारी किया। इस पर भिस कॉल देते ही आपकी सदस्यता दर्ज हो जायेगी।

### संविधान प्रदत्त अधिकार हर हाल में चाहिए

ओबीसी समाज पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार पाने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। संविधान में वर्णित प्रावानाओं के अनुरूप पिछड़ा वर्ग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गांव की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी उसका अमर रोल है। अब ओबीसी समाज एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा और अपना अधिकार लेकर रहेगा।



ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि कुबनी देकर भी हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अब ओबीसी समाज जग गया है। दबेंगे नहीं, हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। झारखंड में ओबीसी की आवादी 65 प्रतिशत है, हर हाल में 52 फीसदी आरक्षण चाहिए। हर नौकरी में 100 में 52 लोग ओबीसी के होने चाहिए। बिहार की तर्ज पर झारखंड में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हालांकि इसकी घोषणा सरकार के स्तर से की गयी है, लेकिन इस पर जल्द पहल हो। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि ओबीसी छात्र-छात्राओं की प्रतिभा पैसें के अभाव में दम तोड़ रही है। एजुकेशन लोन काफ़ी महंगा है। इस पर सरकार को चाहिए कि एजुकेशन लोन देने के बदले लोटाने पर कोई अतिरिक्त इन्टरेस्ट नहीं लगे। छात्रावास में सरकार को यह कहना चाहिए।

### 65 प्रतिशत आवादी है, 52 फीसदी आरक्षण चाहिए

ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि कुबनी देकर भी हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अब ओबीसी समाज जग गया है। दबेंगे नहीं, हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। झारखंड में ओबीसी की आवादी 65 प्रतिशत है, हर हाल में 52 फीसदी आरक्षण चाहिए। हर नौकरी में 100 में 52 लोग ओबीसी के होने चाहिए। बिहार की तर्ज पर झारखंड में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हालांकि इसकी घोषणा सरकार के स्तर से की गयी है, लेकिन इस पर जल्द पहल हो। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि ओबीसी छात्र-छात्राओं की प्रतिभा पैसें के अभाव में दम तोड़ रही है। एजुकेशन लोन काफ़ी महंगा है। इस पर सरकार को चाहिए कि एजुकेशन लोन देने के बदले लोटाने पर कोई अतिरिक्त इन्टरेस्ट नहीं लगे। छात्रावास में सरकार को यह कहना चाहिए।

रांची

सोमवार, वर्ष 09, अंक 141

# आजाद सिपाही

कलम कलम बढ़ाये जा



**FLORENCE**  
Group of Institutions  
(A Unit of Hajj Abdur Razzaque Educational Society)  
Irba, Ranchi-835219, Jharkhand



## न्यूज रील्स

गिरिडीह में जैन समाज के आश्रम से अध्यात्म की सामूहिकता और श्री कृष्ण वार्द्धन उदासीन आश्रम में पाठ्यनाथ भगवान के महिले के गेट का ताला तोड़कर शनिवार रात घोरी ने अध्यात्म एवं पीतल की बनी 12 मूर्तियों सहित अन्य समाजों की चारी कोटी में दिंगबर जैव 20 पंथी कोटी की समीप स्थित श्री कृष्ण वार्द्धन-शिलान्यास और लाभुकों के

मुख्यमंत्री के हाथों जामताड़ा और गिरिडीह को मिली 980.15 करोड़ की सौगत हम घोषणाएं नहीं कर रहे, योजनाओं को जमीन पर उतार रहे: चंपाई सोरेन

### आजाद सिपाही टीम

जामताड़ा/पीरठांडि। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को जामताड़ा और गिरिडीह जिलों को 980.15 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की संोगत दी।

उन्होंने जामताड़ा-निरसा पथ पर वीरग्राम-बर्बेंदिया में बाराकर नदी पर उच्चस्तरीय पुल और गिरिडीह के पीरठांडि में 639.20 करोड़ की मेंगा लिपट सिंचाइ योजना का शिलान्यास

एवं उदासीन आश्रम में पाठ्यनाथ

भगवान के महिले के गेट का ताला तोड़कर शनिवार रात घोरी ने

अध्यात्म एवं पीतल की बनी 12

मूर्तियों सहित अन्य समाजों की

चारी कोटी में दिंगबर जैव 20 पंथी

कोटी की समीप स्थित श्री कृष्ण

वार्द्धन-शिलान्यास और

लाभुकों के

बीच परिसंपत्तियों का वितरण

किया। इसमें 263.87 करोड़ रुपये

की बर्बेंदिया पुल परियोजना और

26 करोड़ रुपये की 12 अन्य

योजनाओं का लोकार्पण और नींव

रखी गयी। वहीं 69631 लाभुकों

के बीच 52.80 करोड़ रुपये की

परिसंपत्तियों का वितरण हुआ।

दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने

कहा कि हमारी सरकार केवल

घोषणाएं नहीं कर रही है,

बल्कि

योजनाओं को धरातल पर उतार

भी रही है। उन्होंने कहा कि बर्बेंदिया

पुल के निर्माण से जामताड़ा समेत

पूरे संताल का धनबाद से रोड कनेक्टिविटी

मजबूत होगा।

हम जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा

करते हैं क्योंकि योजनाएं

नहीं पहुंची हो।

■ जामताड़ा के वीरग्राम-बर्बेंदिया में बाराकर नदी पर 263.87 करोड़ के पुल का शिलान्यास

■ गिरिडीह के पीरठांडि में 639.20 करोड़ की नेगा लिपट सिंचाइ योजना का शिलान्यास

■ आज कोडी नी ऐसा परिवार नहीं है, जहाँ हमारी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं।



### विकास का गलियारा बना रहे

जामताड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत सरकारों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में सड़कों तथा पुल-पलिया का जाल बिछाया जा रहा है, ज्योतिंशुओं के जरिये विकास का नया गलियारा बनाना है। उन्होंने कहा कि बर्बेंदिया उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बराकर नदी में नाव दुर्घटना होने से जल समाधि ले ली थी। उन्होंने कहा कि बर्बेंदिया पुल के निर्माण से जामताड़ा समेत पूरे संताल का धनबाद से रोड कनेक्टिविटी

मजबूत होगा।

हम जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा

करते हैं क्योंकि योजनाएं

नहीं पहुंची हो।

### झारखंड कभी गरीब नहीं रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कभी गरीब नहीं रहा, लिंगन यहाँ के लोग गरीबी में रहने से रहने के बारे में अजबूर रहे। अलग राज्य बनने के 19 वर्षों तक झारखंड के उत्त्यान पर किसी भी सरकार का व्याप नहीं रहा। सिफ़र यहाँ के खिलान संसाधनों का दोहन होता रहा। यहाँ के आदिवासियों-मूलवासियों के दुख-दर्द को किसी ने समझने की करिंशन नहीं की। 2019 में हेमत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने यहाँ के आदिवासियों-मूलवासियों, दलितों, पिछड़ी, अल्पसंख्यक, गरीबों, जस्तरमंडी और किसानों-मजदूरों की समस्याओं को समझा और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाकर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

सहायता के लिए सोचते हैं।

हमारी सरकार घोषणाओं में कहते हैं, उसे अवश्य पूरा करते हैं क्योंकि योजनाएं

नहीं करती हैं। यहाँ के लोगों

नहीं करती हैं।

धरातल पर उतार रही हैं। समाज के अंतिम पर्यांक में बैठें व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है।

पीरठांडि क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा; बाद में मरकर संकरित मेला मेलान, मधुबन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यहाँ के कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाहुपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसान साल भर में फसल की उपज कर सके, यह हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह झारखंड आंदोलन की धरती रही है। दिशेम गुरु शिव सोरेन ने इसी धरती से झारखंड आंदोलन को धारा के लिए राजनीतिक धूमधारों में से एक बनाया। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत 32 वाल्युमेट्रिक प्रोकास्ट विधि से 5.15 एकड़ि में सात इमारतें बनायी गयी हैं। इसके तहत 131 कोडी की लागत से 1024 पर्सेट बनाये गये। होरेक फ्लैट 315 वर्ग फ्लैट में बना कर उन्हें रहाएं और एक बड़े रुम में बैठक बनायी गई।

मोके पर अन्य लोगों के लिए कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा विधायक सुदिक्ष बुमराह, इरकान अंसारी, पूर्व संसदीय विधायक के प्रश्नान्वयन से अवसरा में 1008 पर्सेट बनाये गये। होरेक फ्लैट 315 वर्ग फ्लैट में बना कर उन्हें रहाएं और एक बड़े रुम में बैठक बनायी गई।

मोके पर अन्य लोगों के लिए सेट

ने कहा कि वह फ्लैट महज

प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी

की गर्भांशी देवी है।

प्रधानमंत्री की गर्भांशी देवी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी

की गर्भांशी देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।

प्रधानमंत्री का गर्भांशी

देवी है।













# संपादकीय

## घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि

ये जनाओं को शुरू करके महिलाओं को सशक्त बनायें, ताकि महिलाएं विभिन्न विषयों में अपनी जगह बनाने में सक्षम हो सकें, जिसके लिए केंद्र सरकार उनकी बेहतरी के लिए रास्ते बना कर हरसंभव प्रयास कर रही है, लेकिन प्राथमिकता अच्छी शिक्षा प्रदान करने पर ही ही चाहिए। किसी भी चीज से पहले घर, बाहर और काव्यस्थल पर महिलाओं को सुक्ष्म सुनिश्चित करने पर जो दिया जाना चाहिए। तब तक लड़कियां अपने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक वे कुछ नहीं कर पायेंगी। आजकल हर दूसरे दिन दुक्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दुख की बात है कि बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, हरियाणा की आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना, सभी कागजों में हैं। लड़कियों के खिलाफ क्रूरता की खून जमा देने वाली घटनाएं रोजाना सामने आती हैं और

हर मामला दूसरे से कम धन्यवादी नहीं होता। जहां तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की आगीदारी का सवाल है,

उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। वर्तमान में प्रतिनिधित्व नामांत्रण का बिल पारित किया है, जिसे सभी नेतृत्वकार कर लिया है। इसके अलावा महिलाएं समुदाय की जरूरतों को बेहतर ढंग से जानती हैं और कोई भी समाज जो महिलाओं को बाहर कर देता है, वह आपांत्की से ज्यादा प्रतिभा, क्षमता और उसके पास मौजूद संसाधनों को बाहर कर देता है। लेकिन महिलाओं द्वारा आपांत्की से ज्यादा प्रतिभा, क्षमता और उसके साथ मौजूद संसाधनों को बाहर कर देता है। इसके अलावा भवित्व के लिए अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। इन सबके बावजूद घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि एक बड़ी समस्या प्रतीत होती है। घरेलू हिंसा एक ऐसा विषय है, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना या इसके बारे में बोलना पसंद करते हैं। हमारे घरों में पिंपुस्ता व्यापार है और







